सीएम ने किया बड़ाम-जराटोली स्थित विधिक सेवा केंद्र का शिलान्यास, कहा

08-11-16 , प्रत्यूष नव-बिहार

गरीबी हटाना हमारा लक्ष्य

संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही राज्य का विकास हो सकता है। केवल सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराना ही विकास समूचित विकास नहीं है। झारखंड से गरीबी समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य है। इसके लिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा कर लोगों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अब गरीब के नाम पर गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज बड़ाम-जराटोली स्थित कानूनी सेवा केंद्र का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस गांव को राज्यसभा सांसद श्री परिमल नाथवाणी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कानूनों का सरलीकरण किया गया है। कुछ लोग इस पर राजनीति करने से बाज

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्जवलित करते मुख्यमंत्री।

नहीं आ रहे हैं। राज्य के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल राजनीति करनी है। अपने शासनकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब सरकार काम कर रही है, तो सवाल उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस पहल की गयी है। राज्य के 30 हजार स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है। गांव के ही कारपेंटरों को एक मॉडल देकर बेंच-डेस्क बनाने का आर्डर दिया। वे अपने आस पास के स्कूलों में बेंच-डेस्क की सप्लाई करेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति से उन्हें राशि मिलेगी। इस एक काम से राज्य के गांवों में 400 करोड़ रुपये आयेंगे। इसी तरह बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को मुर्गीपालन से जोड़ा जा रहा है। मुर्गीपालन से उत्पादित अंडों को नजदीकी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खरीदा जायेगा। साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी इनकी खरीद की जायेगी। झारक्राफ्ट से स्थानीय महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित कर कंबल, परदे, तौलिये, तकिया का खोल, चादर आदि बनवाई जायेगी। इनकी सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी खरीद को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। शिक्षित गांव से ही विकसित गांव बन सकेगा। बेटा-बेटी में फर्क न करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का काम शुरू हो चुका है। काम में तेजी आ रही है। धैर्य रखे। अगले 2-3 साल में बदलाव दिखेगा। लोगों के मुरझाये चेहरे पर मुस्कान आये, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। गरीबी समाप्त करना अकेले किसी के वश में नहीं है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए हर ब्लॉक में स्कील डेवलेपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। श्री दास ने कहा कि यह कानूनी सलाह केंद्र देश का पहला केंद्र है, जहां लोगों को कानूनी सलाह और सेवाएं मिलेंगी। सरकार और न्यायपालिका का एक मात्र काम गरीबों को न्याय दिलाना है। यह केंद्र राज्य ही नहीं देश में रोल मॉडल बनेगा।

नामकुम के बड़ाम-जराटोली में कानूनी सेवा केन्द्र का शिलान्यास, बोले मुख्यमंत्री

राज्य से गरीबी समाप्त करना मुख्य लक्ष्य

वरीय संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही पूरे राज्य का विकास हो सकता है। सिर्फ सड़कें, बिजली, पानी उपलब्ध कराना ही समुचित विकास नहीं है। झारखंड से गरीबी समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य है। इसके लिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा कर लोगों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अब गरीब के नाम पर गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सोमवार को नामकुम प्रखंड अंतर्गत बड़ाम-जराटोली स्थित कानूनी सेवा केंद्र का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस गांव को राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कानूनों का सरलीकरण किया गया है। कुछ लोग इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्य के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल राजनीति करनी है। अपने शासनकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब सरकार काम कर रही है, तो सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस पहल की गयी है। राज्य के 30 हजार स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है। गांव के ही कारपेंटरों को एक मॉडल देकर बेंच-डेस्क बनाने का आर्डर दिया। वे अपने आस पास के स्कूलों में बेंच-डेस्क की सप्लाई करेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति से उन्हें राशि मिलेगी। इस एक काम से राज्य के गांवों में 400 करोड़ रुपये आयेंगे। इसी तरह बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुर्गीपालन से जोड़ा जा रहा है। मुर्गीपालन से उत्पादित अंडों को नजदीकी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खरीदा जायेगा। साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी इनकी खरीद की जायेगी। झारक्राफ्ट से स्थानीय महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित कर कंबल, परदे, तौलिये, तकिया का खोल, चादर आदि बनवाई जायेगी। इनकी सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी खरीद को प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। शिक्षित गांव से ही विकसित गांव बन सकेगा। बेटा-बेटी में फर्क न करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का काम शुरू हो चुका है। काम में तेजी आ रही है। धैर्य रखे। अगले 2-3 साल में बदलाव दिखेगा। लोगों के मुरझाये चेहरे पर मुस्कान आये, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। गरीबी समाप्त करना अकेले किसी के वश में नहीं है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए हर ब्लॉक में स्कील डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। श्री दास ने कहा कि यह कानूनी सलाह केंद्र देश का पहला केंद्र है, जहां लोगों को कानूनी सलाह और सेवाएं मिलेंगी। सरकार और न्यायपालिका का एक मात्र काम गरीबों को न्याय दिलाना है। यह केंद्र राज्य ही नहीं देश में रोल मडल बनेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल, विधायक रामकुमार पाहन, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

60 लाख की लागत से तीन हजार वर्गफीट में बनेगा दो मंजिला भवन

राज्य सभा सांसद परिमल नथवाणी सांसद आदर्श गांव योजना तहत करेंगे लिगल सर्विसेज क्लिनिक का निर्माण

वरीय संवाददाता

रांची : नामकुम के बड़ाम-जराटोली पंचायत में कानूनी सेवा केन्द्र का निर्माण राज्य सभा सांसद परिमल नथवाणी द्वारा सांसद आदर्श गांव योजना तहत किया जायेगा। कानूनी सेवा केन्द्र का संचालन झारखंड स्टेट लिगल सविर्सेज अथॉरिटी द्वारा किया जायेगा। इस कानूनी सेवा केन्द्र का निर्माण 60 लाख की लागत से 3,000 वर्गफीट में होगा। दो मंजिला इमारत में नीचे के तल पर न्यायाधीश का कमरा और वकीलों के लिए दो कमरें रहेंगे। नीचे के तल पर महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय, फोयर, नोटिस बोर्ड, रिकॉर्ड रूम और पैंट्री जैसी सुविधा उपलब्ध होंगी। प्रथम तल पर, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, काउंसेलिंग रूम की व्यवस्था के साथ स्वयंसेवको के लिए दो कमरें और शौचालय की सुविधा भी होगी। इस इमारत में दो कार के साथ-साथ अनेक दो पहियां वाहन पार्क करने की भी सुविधा होगी। इस अवसर पर राज्य सभा सांसद परिमल नथवाणी ने बताया कि मुझे बेहद खुशी है कि झारखंड का सब से पहला कानूनी सेवा केन्द्र बड़ाम पंचायत के अंतर्गत बन रहा है। खुशी इसलिए भी कि बडाम पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम योजना तहत मैंने गोद लिया है।. कानूनी सेवा केन्द्र में महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगो, कैदियों और समाज के पिछड़े वर्गो के लोगों को एक ही स्थान पर मुफ्त में कानूनी मदद का लाभ मिलेगा।

सांसद निधि से बड़ाम पंचायत का हुआ कायाकल्प

सांसद निधि से बड़ाम पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक भवन, स्कूल, स्वास्थ्य उप-केन्द्र, शौचालय, सड़कें, पानी की सुविधा आदि कार्य व्यापक जनहित में किया है और लोगों को इनका इस्तमाल करने की अपील की। श्री नथवाणी ने मुख्य मंत्री रघुबर दास से मॉडल स्कूल, रांची को पुरुलिया से जोड़नेवाली 14 कि.मी. लंबी सड़क, बडाम और हरा घाट को जोडने वाली 1.5 कि.मी. लंबी सड़क, बड़ाम पंचायत में सैंक्शन हुए 642 टॉयलेट और अगले सांसद आदर्श गांव में सैंक्शन हुए 450 टॉयलेट, आदि काम में तेजी लाने की अपील की। श्री नथवाणी ने बडाम पंचायत में बन रहे फूटबॉल स्टेडियम और बडाम व चुटटु पंचायल क्षेत्र में अलग-अलग जगह पर बन रहे 6 चेक डैम के कार्य तेजी से शुरु करने की भी अपील की। श्री नथवाणी ने झारखंड से दूसरी बार राज्य सभा में चुने जाने पर 2014 में ही बड़ाम-जराटोली में विकास कार्यो का प्रारंभ कर दिया था और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अक्तूबर 11, 2014 को सांसद आदर्श गांव योजना की घोषणा के साथ बड़ाम पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। श्री नथवाणी ने बडाम पंचायत क्षेत्र में सभा घर, बाल उद्यान, सरना स्थल और मराई स्थल के सुरक्षा इंतजाम के लिए बाउन्ड्री वाल आदि का निर्माण कराया है। जलापूर्ति के लिए पानी की टंकी, सार्वजनिक टॉयलेट व दो एंबुलेंस भी उपलब्ध कराए हैं। सांसद निधि से स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण कराया और उसमें पीने के पानी हेतु बोरवेल भी लगवाया है। श्री नथवाणी ने पीने का पानी घरों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी लगवाई है। सांसद निधि से बडाम मे टाटीसिलवे प्राइमरी स्कूल के ग्राउंडऔर प्रथम तल का निर्माण, बाउन्ड्री वॉल, पेविंग विस्तार का निर्माण किया व जराटोली में टॉयलेट और रसोई घर का निर्माण भी कराया।

बंद होनी चाहिए गरीबी के नाम पर राजनीति : रघुवर

संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही राज्य का विकास हो सकता है। केवल सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराना ही समूचित विकास नहीं है। झारखंड से गरीबी समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य है। इसके लिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा कर लोगों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अब गरीब के नाम पर गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सोमवार को बड़ाम-जराटोली स्थित कानूनी सेवा केंद्र का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस गांव को राज्यसभा सांसद श्री परिमल नाथवाणी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कानूनों का सरलीकरण किया गया है। कुछ लोग इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्य के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल राजनीति करनी है। अपने शासनकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब सरकार

कानूनी सेवा केंद्र का शिलान्यास करते रघुवर दास व अन्य।

काम कर रही है, तो सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री दास ने कहा कि लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस पहल की गयी है। राज्य के 30 हजार स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है।

गांव के ही कारपेंटरों को एक मॉडल देकर बेंच-डेस्क बनाने का आर्डर दिया। वे अपने आस पास के स्कूलों में बेंच-डेस्क की सप्लाई करेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति से उन्हें राशि मिलेगी। इस एक काम से राज्य के गांवों में 400 करोड़ रुपये आयेंगे। इसी तरह बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुर्गीपालन से जोड़ा जा रहा है। मुर्गीपालन से उत्पादित अंडों को नजदीकी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खरीदा जायेगा। साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी इनकी खरीद की जायेगी। झारक्राट से स्थानीय महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित कर कंबल, परदे, तौलिये, तकिया का खोल, चादर आदि बनवाई जायेगी। इनकी सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी खरीद को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। शिक्षित गांव से ही विकसित गांव बन सकेगा। बेटा-बेटी में फर्क न करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का काम शुरू हो चुका है। काम में तेजी आ रही है। धैर्य रखे। अगले 2-3 साल में बदलाव दिखेगा। लोगों के मुरझाये चेहरे पर मुस्कान आये, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। गरीबी समाप्त करना अकेले किसी के वश में नहीं है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए हर ब्लॉक में स्कील डेवलेपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। दास ने कहा कि यह कानूनी सलाह केंद्र देश का पहला केंद्र है, जहां लोगों को कानूनी सलाह और सेवाएं मिलेंगी। सरकार और न्यायपालिका का एक मात्र काम गरीबों को न्याय दिलाना है। यह केंद्र राज्य ही नहीं देश में रोल मॉडल बनेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री परिमल नाथवाणी, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी0एन0 पटेल, विधायक श्री रामकुमार पाहन, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

आज रांची, मंगलवार ८ नवम्बर २०१६

गरीबी के नाम पर बंद हो गंदी राजनीति

छाया : अखिलेश

कानूनी सेवा क्लीनिक का शिलान्यास करते रघुवर दास, साथ में न्यायमूर्ति डीएन पटेल व सांसद परिमल नथवाणी।

रांची, 7 नवंबर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही राज्य का विकास हो सकता है। केवल सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराना ही समुचित विकास नहीं है। झारखंड से गरीबी समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य है। इसके लिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा कर लोगों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अब गरीब के नाम पर गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज रांची जिले के बड़ाम-जराटोली में कानूनी सेवा केंद्र का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस गांव को राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कानूनों का सरलीकरण किया गया है। कुछ लोग इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्य के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल राजनीति करनी है। अपने शासनकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब सरकार काम कर रही है, तो सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री दास ने कहा कि लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस पहल की गयी है। राज्य के 30 हजार स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है। गांव के ही कारपेंटरों को एक मॉडल देकर बेंच-डेस्क बनाने का आर्डर दिया। वे अपने आस पास के स्कूलों में बेंच-डेस्क की सप्लाई करेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति से उन्हें राशि मिलेगी। इस एक काम से राज्य के गांवों में 400 करोड़ रुपये आयेंगे। इसी तरह बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुर्गीपालन से जोड़ा जा रहा है। मुर्गी पालन से उत्पादित अंडों को नजदीकी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खरीदा जायेगा। साथ ही सरकार अस्पतालों में भी इनकी खरीद की जायेगी। झारक्राफ्ट से स्थानीय महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित कर कंबल, परदे, तौलिये, तकिया का खोल, चादर आदि बनवाई जायेगी। इनकी सरकार खरीद के साथ-साथ निजी खरीद को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। शिक्षित गांव से ही विकसित गांव बन सकेगा। बेटा-बेटी में फर्क न करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का काम शुरू हो चुका है। काम में तेजी आ रही है। धैर्य रखे। अगले 2-3 साल में बदलाव दिखेगा। लोगों के मुरझाये चेहरे पर मुस्कान आये, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। गरीबी समाप्त करना अकेले किसी के वश में नहीं है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए *(शेष पृष्ठ ९ पर)*

गरीबों के नाम पर...

हर ब्लॉक में स्कील डेवलेपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कानूनी सलाह केंद्र देश का पहला केंद्र है, जहां लोगों को कानूनी सलाह और सेवाएं मिलेंगी। सरकार और न्यायपालिका का एक मात्र काम गरीबों को न्याय दिलाना है। यह केंद्र राज्य ही नहीं देश में रोल मॉडल बनेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल, विधायक रामकुमार पाहन, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

रांची, 08 नवंबर
2016

राज्य से गरीबी खत्म करना पहला लक्ष्य : मुख्यमंत्री

संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही राज्य का विकास हो सकता है। केवल सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराना ही विकास समुचित विकास नहीं है। झारखंड से गरीबी समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य है। इसके लिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा कर लोगों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अब गरीब के नाम पर गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज बड़ाम-जराटोली स्थित कानूनी सेवा केंद्र का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस गांव को राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कानूनों का सरलीकरण किया गया है। कुछ लोग इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्य के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल राजनीति करनी है। अपने शासनकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब सरकार काम कर रही है, तो सवाल उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस पहल की गयी है। राज्य के 30 हजार स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है। गांव के ही कारपेंटरों को एक मॉडल देकर बेंच-डेस्क बनाने का आर्डर दिया। वे अपने आस पास के स्कूलों में बेंच-डेस्क की सप्लाई करेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति से उन्हें राशि मिलेगी। इस एक काम से राज्य के गांवों में 400 करोड़ रुपये आयेंगे। इसी तरह बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुर्गीपालन से जोड़ा जा रहा है। मुर्गीपालन से उत्पादित अंडों को नजदीकी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खरीदा जायेगा। साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी इनकी खरीद की जायेगी। झारक्राफ्ट से स्थानीय महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित कर कंबल, परदे, तौलिये, तकिया का खोल, चादर आदि बनवाई जायेगी। इनकी सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी खरीद को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। शिक्षित गांव से ही विकसित गांव बन सकेगा। बेटा-बेटी में फर्क न करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का काम शुरू हो चुका है। काम में तेजी आ रही है। धैर्य रखे। अगले 2-3 साल में बदलाव दिखेगा। लोगों के मुरझाये चेहरे पर मुस्कान आये, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। गरीबी समाप्त करना अकेले किसी के वश में नहीं है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए हर ब्लॉक में स्कील डेवलेपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है।

श्री दास ने कहा कि यह कानूनी सलाह केंद्र देश का पहला केंद्र है, जहां लोगों को कानूनी सलाह और सेवाएं मिलेंगी। सरकार और न्यायपालिका का एक मात्र काम गरीबों को न्याय दिलाना है। यह केंद्र राज्य ही नहीं देश में रोल मॉडल बनेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल, विधायक रामकुमार पाहन, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

the pioneer
RANCHI | TUESDAY | NOVEMBER 8, 2016

Politics over the poor must be stopped in Jharkhand: CM

Foundation laid for first Legal Service Clinic at Namkom

PNS ■ RANCHI

Chief Minister Raghubar Das today said that the primary motive of his Government was to remove poverty from the State by making people self-dependent after creating avenues of employment in the villages itself. Das was addressing a gathering after laying the foundation stone for Legal Service Clinic at Badam-Jaratoli in Namkom near Ranchi on Monday.

"Politics over the poor must be stopped in this state," said the CM. Das also added that development of State could be brought only with the development of the individuals as providing electricity, water and roads to the people was not the only parameter of development.

"Acts are being simplified in the State to develop essential infrastructure but people have started doing politics on it. They (Opposition) do not have to do anything with the development, they are interested in doing politics only," said the CM. They did not do anything during their regime, but are now questioning the government which had been trying to do something in this regard, he added. The legal service clinic will be set up by Rajya Sabha Member Parimal Nathwani who has adopted the village under Saansad Adarsh Gram Yojana. It will be set up in association with Jharkhand State Legal Service Authority. Judge of Jharkhand High Court and Executive Chairman of Jharkhand Legal Service Authority (JHALSA) Justice DN Patel and other dignitaries also graced the occasion with their presence. The Legal Services Clinic will be constructed on 3,000 square feet area at the cost of Rs 60 lakh. The two-storied building will have a chamber for a judge and two chambers for lawyers on the ground floor. It will also have separate waiting Lounges for ladies and gents with toilet blocks, entrance foyer, notice board space, record room and canteen.On the first floor, there will be auditorium cum conference room cum counseling class room along with two rooms for the volunteers and toilet blocks. The paved parking area will accommodate two cars and several two-wheelers. Speaking on the occasion, Nathwani said, "I am pleased to announce that first Legal Services Clinic has been built in Baram Panchayat, which is adopted by me under Saansad Adarsh Gram Yojana. This is one of the humble efforts to realize the dream and vision of our Prime Minister Narendra Modi about model village."

Chief Minister Raghubar Das, along with Judge Jharkhand High Court Justice DN Patel and Rajya Sabha MP Parimal Nathwani, lights the lamp during inaugural ceremony of Legal Service Centre at Badam near Ranchi on Monday. Pioneer

"Legal Services Clinic is an 'One Stop Centre' to ensure easy and free access to justice to women, children, differently abled persons, prisoners and all the persons belonging to most marginalized section of society", said Nathwani.

The Rajya Sabha MP also requested Chief Minister to instruct the concerned departments to expedite the construction of model school and construction of 14 km long road connecting Ranchi and Purulia and 1.5 km road from Hara Ghat to Baram. He also informed that 624 toilets have been sanctioned in Baram Panchayat and 450 toilets in Chuttu Panchayat, which is his next Adarsh Village under SAGY, and requested to expedite the work so that people can use toilets. Nathwani also asked the Chief Minister to instruct the concerned officials to start construction work of football stadium in Baram Panchayat area and 6 check dams at different locations in Baram and Chuttu Panchayat at the earliest

Every individual matters in developing Jharkhand: CM

MI News Service

RANCHI: Jharkhand Chief Minister Raghubar Das believes that the actual development of state is possible through development of each individual. Developed state can be a reality when all have jobs and everyone feels independent and lives without fear.

He said development does not come from construction of roads, providing electricity and water to people alone.

He said this while addressing people on Monday during an event at legal service center in Badam-Joratoli here.

He said for development of the place, the state government has done some simplification in the laws. Targeting the opposition parties, he said during their time in power, they hardly did anything and now they are continuously playing politics in every decision of the present government. They are not allowing the present government to work properly, Das said.

The CM stressed on making people independent and said till now there is a shortage of 30 thousand benches and desks in the government schools of the state.

He said to overcome the issue, the government has provided model of bench and desk to the local carpenters of villages who are asked to supply the items to the schools in their villages. He said through this job, each village will earn about Rs 400 crore.

He said those who own poultry farms can supply the eggs to schools in their villages for the mid-day meal programme as well as the hospitals can purchase the eggs from them.

Das urged the women to send their children to schools because they are the future of country adding if they will be educated then only villages can develop faster. He said works for development of state have been started and the results will be visible in two to three years.

The CM said the legal service center is the first legal consultation center of the country where people can get legal advices. He said this center will become role model for other states of the country.

Rajya Sabha MP Parimal Nathwani, Executive President Justice D N Patel, MLA Ramkumar Pahan and other dignitaries were present during the event.